कोसी इलाके में चार नदियों पर बनेंगे पुल, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

संवाददाता, पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को स्टेट हाइवे- 95 और इंडो-नेपाल बॉर्डर का एरियल सर्वे किया. इस दौरान उन्होंने बागमती, कमला, मृत कोसी और कोसी नदियों पर बनने वाले चार पुलों के एलाइनमेंट का निरीक्षण किया. इसके बाद इन पुलों के निर्माण को मंजूरी दी. इसकी डीपीआर तैयार कर ली गयी है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 1400 करोड़ रुपये हैं.

सीएम ने स्टेट हाइवे- 95 और इंडो-नेपाल बॉर्डर का किया एरियल सर्वे, प्रस्ताव को दी मंजूरी

1400 करोड़

होंगे खर्च चारों पुलों पर, डीपीआर हो चुकी है तैयार

552 किमी

लंबी सड़क बनेगी मदनपुर से गलगलिया तक इंडो-नेपाल बॉर्डर पर

नक्शे में कुछ इस तरह दिख रहा इंडो-नेपाल बॉर्डर पर होने वाला निर्माण.

सीएम ने इन स्थानों का किया एरियल सर्वे

स्टेट हाइवे-95 का निर्माण-मानसी (एनएच-31)-सहरसा, हरदी चौघड़ा पथ (स्टेट हाइवे-95), खगड़िया जिला के एनएच- 31 के मानसी से शुरू होकर सहरसा और मधेपुरा जिला होते हुए सुपौल जिला अंतर्गत एसएच- 66 पर हरदी चौघड़ा में मिलती है. इसकी लंबाई 75 किमी है.

मानसी से करीब साढ़े सात किमी (बदलाघाट) तक सिंगल लेन पथ है, जिस पर यातायात चालू है. बदलाघाट से करीब 15.50 किमी फनगो हाल्ट तक वर्तमान में पथ का कोई एलाइनमेंट नहीं है. यह एक मिसिंग लिंक है. इसे जोड़ने के लिए चार पुलों का निर्माण होने जा रहा है.

सीएम ने इसका निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया. इन नदियों पर वर्तमान में रेल पुल है, जिस पर रेल परिचालन होता है. इसके अलावा सड़क पुल बन जाने से इस क्षेत्र में मिसिंग लिंक खत्म हो जायेगा और सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया समेत अन्य जिलों के नागरिकों को पटना आने में काफी सहूलियत होगी. पर्यटन के दृष्टिकोण से कात्यायनी मंदिर पर आवागमन बेहद सुगम हो जायेगा. वर्तमान में यहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ नाव से ही है. खगड़िया और सहरसा के सबसे दुर्गम क्षेत्र में आवागमन कायम हो पायेगा.

इसके अलावा इंडो नेपाल बॉर्डर पर पश्चिम चंपारण के मदनपुर से यह सड़क शुरू होकर किशनगंज के गलगलिया तक जायेगी. इसकी कुल लंबाई 552 किमी है. यह सड़क सात जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से गुजर रही है. इन जिलों की 365 गांवों में दो हजार 894 एकड़ भूमि का अधिग्रहण इस सड़क के निर्माण में किया जा रहा है. राज्य के अनुरोध पर केंद्र ने इस योजना को पूर्ण करने की संशोधित अवधि मार्च 2022 तक रखी गयी है. इस सड़क में अब तक 93 किमी का कार्य पूरा हो चुका है. पूरी योजना पर एक हजार 702 करोड़ की लागत आयेगी. राज्य सरकार भू-अर्जन पर दो हजार 233 करोड़ रुपये और पुल निर्माण पर 983 करोड़ यानी कुल तीन हजार 216 करोड़ रुपये खर्च कर करेगी. इस योजना के सुपौल जिले में पड़ने वाले हिस्से भपटियाही से वीरपुर का एरियल सर्वे मुख्यमंत्री ने किया. जहां दो लेन का उत्कृष्ट पथ बन गया है. मुख्यमंत्री ने अन्य जिलों के काम में तेजी आने का भी निर्देश दिया.